भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या97*

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

छह जिलों में माओवादी गतिविधियों का मुकाबला करने पर ध्यान दिया जाना

***97. डॉ0 के.पी. रामलिंगमः**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छह जिलों में माओवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि सर्वाधिक प्रभावित चार राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में, सरकार ने माओवादियों के विरुद्ध संयुक्त सुरक्षा कार्रवाई किए जाने का सुझाव दिया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 04.03.2015 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 97 के भाग(क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी, नहीं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए केन्द्र सरकार की 'सुरक्षा संबंधी व्यय' योजना में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों के 106 जिले वामपंथी उग्रवादी हिंसा का मुकाबला करने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किए जाने हेतु शामिल किए गए हैं। तथापि, रणनीतिक कारणों से विशिष्ट क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इस संबंध में, गृह मंत्रालय ने हाल में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित चार राज्यों में सर्वाधिक प्रभावित कतिपय जिलों की समीक्षा की है।

(ग) और (घ): जी , हां। वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित कतिपय जिलों में वामपंथी उग्रवाद की चुनौती की समीक्षा और निगरानी करने के लिए नई दिल्ली में दिनांक 09.02.2015 को केन्द्रीय मंत्रालयों के मंत्रियों तथा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों एवं तेलंगाना और ओडिशा के पदाधिकारियों के साथ केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक के दौरान , सुरक्षा परिदृश्य में सुधार लाने तथा छत्तीसगढ़ तथा इससे लगे ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना के जिलों में विकास के संबंध में किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के बारे में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

****